भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1450
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा की समीक्षा

1450. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की समीक्षा से पता चला है कि कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या में 8.6% की वृद्धि के साथ कवरेज में वृद्धि हुई है;
(ख) क्या यह भी सच है कि समीक्षा से यह भी पता चला है कि वादा किए गए रोजगार की आपूर्ति में कमी आई है और कार्य दिवसों में 7.1% की गिरावट आई है;

(ग) क्या विलंबित मजदूरी मनरेगा कवरेज और वितरण के बीच बेमेल का एक प्रमुख कारक है;

(घ) क्या केंद्र सरकार द्वारा कम बजट आवंटन ने मनरेगा की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में पंजीकृत परिवारों की संख्या और सृजित श्रम दिवसों का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित श्रम दिवस
2023-24	14.81	312.16
2024-25	15.99	290.60

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और एक विकल्प है जब रोजगार का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं हो। भारत सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मांग के अनुसार इच्छुक पात्र ग्रामीण परिवारों को उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (22.07.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, रोजगार की मांग करने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों में से 99.79% को रोजगार की पेश्कश की गई है।

केंद्र सरकार ने इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें शामिल हैं, (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए दीवार पेंटिंग सहित उचित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना , (ii) मांग पंजीकरण प्रणाली के दायरे और कवरेज का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य की मांग अपंजीकृत न रहे , (iii) भागीदारी मोड में योजनाएं तैयार करना और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करना, (iv) 'रोजगार दिवस' का आयोजन करना।

(घ) और (ड़.): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था , जो कि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बजट अनुमान (बीई) चरण में योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन था। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने इस आवंटन को 86,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है , जिससे ग्रामीण रोजगार के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी।

योजना की मांग आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग पर गहनता से नजर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग करता है। इस योजना के अंतर्गत निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग के अनुसार निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 23.07.2025 की स्थिति के अनुसार 45,783 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है , जिसमें से 37,912 करोड़ रुपये मजदूरी के भुगतान के लिए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई मजदूरी देयता लंबित नहीं है।